

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या: 1999
उत्तर देने की तारीख: 11.03.2025

पश्चिम बंगाल में समाज कल्याण कार्यक्रम

1999. श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजनों सहित सीमांत समुदायों की सहायता करने के उद्देश्य वाले सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) राज्य में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या पहल की गई है;
- (ग) पश्चिम बंगाल में वंचित समूहों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख और रोजगार तक पहुंच में सुधार के लिए क्या उपाय लागू किए जा रहे हैं; और
- (घ) राज्य के भीतर सामाजिक समावेशन को बढ़ाने और आर्थिक असमानताओं को कम करने के उद्देश्य वाले कार्यक्रमों की प्रगति क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दिव्यांग व्यक्तियों सहित लाभवंचित समुदायों के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना, आर्थिक असमानताओं को कम करना, तथा पश्चिम बंगाल राज्य सहित पूरे देश में वंचित समूहों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों की उपलब्धता में सुधार करना है। इन योजनाओं का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई पहल की हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

दिनांक 11.03.2025 को श्री जगन्नाथ सरकार द्वारा लोक सभा में उत्तर के लिए नियत अतारंकित प्रश्न संख्या 1999 के भाग (क से घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजनाएं
1	अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
2	अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री मैट्रिक
3	यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस)
4	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)
5	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए तंत्र का सुदृढीकरण
6	लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा स्कीम (श्रेष्ठ)
7	राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते)
8	अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड
9	पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड
10	अनुसूचित जाति के लिए प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (पीएम-दक्ष)
11	अन्य पिछड़े वर्ग के लिए प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (पीएम-दक्ष)
12	अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईआई)
13	ड्रग्स की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना
14	आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल)
15	वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (पीएम-यशस्वी) (ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी)
16	यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस) (ओबीसी)
17	डीएनटी/एन/एसएन के आर्थिक सशक्तिकरण की स्कीम (सीड)
18	सूचना, निगरानी मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजनाएं
1	दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)
2	प्री-मैट्रिक (कक्षा IX और X),
3	पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा ग्यारह से स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा),
4	उच्च श्रेणी की शिक्षा (शिक्षा में उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा),
5	राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (विदेशी विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री/पीएचडी),
6	दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल. और पी.एच.डी.),
7	निःशुल्क कोचिंग (ग्रुप क और ख पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं और तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं के लिए)।
8	कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना
9	दिव्यांगजन कौशल विकास
10	दिव्यांगजन रोजगार सेतु
11	दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण और जीवन सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडीआईपी)

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजनाएं
1	प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)
2	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)
3	प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)
4	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
5	पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
6	राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना
7	राष्ट्रीय फेलोशिप योजना (एनएफएसटी)
8	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (उच्च श्रेणी)
9	अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
10	अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री मैट्रिक
11	युवा अचीवर्स योजना के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना (श्रेयस)
12	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)
13	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए तंत्र का सुदृढीकरण
14	लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा स्कीम (श्रेष्ठ)
15	अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड
16	अनुसूचित जाति के लिए प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (पीएम-दक्ष)

दिनांक 11.03.2025 को श्री जगन्नाथ सरकार द्वारा लोक सभा में उत्तर के लिए नियत अतारकित प्रश्न संख्या 1999 के भाग (क से घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-1।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम/योजनाएँ:

क्र.सं.	पहल/योजनाएं
1	मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 में यथा संशोधित
2	वेतन संहिता 2019; औद्योगिक संबंध संहिता 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता 2020
3	सक्खी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास)
4	पालना
5	महिला सशक्तिकरण केन्द्र (एचईडब्ल्यू)
6	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)
7	स्टैंड अप इंडिया
8	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
9	दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
10	प्रधानमंत्री आवास योजना
11	सुकन्या समृद्धि योजना
12	कौशल उन्नयन एवं महिला कॉयर योजना
13	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
14	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा)

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु पहल:

1	जमीनी स्तर पर महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की हैं।
2	2023 में, भारत की संसद ने संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2003, “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” पारित किया

महिला शिक्षा के लिए पहल/योजनाएँ:

1	समग्र शिक्षा
2	नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम-एनआईएलपी)
3	स्वच्छ विद्यालय मिशन
4	विज्ञान ज्योति
5	संस्थान परिवर्तन के लिए लैंगिक उन्नति (गति), 2020
6	महिला प्रौद्योगिकी पार्क (2017-18)
